(SHRI JAYANTILAL V1RCHAND BHAI SHAH); (a) Former Economic & Statistical' Adviser- who was also a member of the High Powered Com-mitee on. Agricultural Polices and Programmes, has submitted a note of dissent on 'Farm Price' issue;

(b) Difference of opinion has been expressed on the observations made by the Commitees regarding the following important matters:

(i) Terms of Reference of the Commission for Agricultural Costs and Prices,.

(ii) Formula for arriving at Price Policy,.. '...

(iii) Reliability of Cost of Production estimates and. factors taken into account while calculating such cost,

(iv) Recommendations of Expert? Committee for Review of Methodology of Cost of Production of crops regarding statutory minimum wages being made the basis for estimating the cost of Production.

(c) The Recommendations of the Committee including the note of dissent are under examination.

दालों का उत्पादन

1134. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा**
डा० जितेन्द्र कुमार जन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1950-51 में देश में दालों का उत्पादन 8.4 मिलियन मीट्रिक टन था और वर्ष 1988-89 में इसका उत्पादन बढ़कर 13.7 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले दो दशकों में दालों की खेती का क्षेत्रफल कम हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो छठे, सातवें और आठवें दशक के अंत में कितनी भूमि पर दालों की खेती की जा रही थी ; और

(घ) क्या दालों के उत्पादन में वृद्धि के लिए कोई विशेष प्रयास और अनुसंधान कार्य किये गये हैं यदि हां, तो इस संबंध में ब्योरा क्या है और देश के किन-किन क्षेत्रों में इन अनुसंधानों का उपयोग किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) 1950-51 में दालों का उत्पादन 8.4 मिलियन मीटरी टन था । यह बढ़कर 1988-89 में 13.85 मिलियन मीटरी टन हो गया है ।

(ख) पिछले दो दशकों में देश में दालों की खेती के अधीन आने वाले क्षेत्र में कमी नहीं आयी है । इसमें 20.92 मिलियन हैक्टेयर और 244.45 मिलियन हैक्टेयर के बीच उतार-चढ़ाव होता रहा है ।

(ग) सातवें, आठवें और नवें दशकों की समाप्ति के वर्षों के दौरान दालों के अधीन निम्नांकित क्षेत्र रहा है :

वर्ष	दालों के अधीन क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)
1969-70	22.04
1979-80	22.26
1989-90	23.22

(घ) उन्नत बीजों, पौध रक्षण उपायों, उन्नत उपस्करों और प्रदर्शनों को शामिल करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है । दालों के लिए विशेष खाद्य उत्पादन कार्यक्रम में मुख्य दाल उत्पादक राज्यों में ग्रीष्मकालीन दालों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में विस्तार और चना और अरहर के पौध रक्षण के लिए प्रोत्साहन देना शामिल है ।

दालों के संबंध में अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के [illegible] शोध केन्द्रों और [illegible] कि विश्व विद्या [illegible] 3

किया जा रहा है इसके परिणामस्वरूप 7वीं योजना के दौरान चने की 17, अरहर की 7, मूंग की 8, मटर की 5, मसूर की 4 किस्में और उड़द, मोठ और लोबिया प्रत्येक की दो-दो किस्में विकसित की गई हैं । इन किस्मों के प्रजनक आधारों और प्रमाणीकृत बीजों का उत्पादन और वितरण प्रारंभ किया गया है ।

उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में अरहर, मूंग, उड़द और लोबिया की अल्पावधि किस्मों को आरंभ करके बहुसस्य पद्धति के संवर्धन में ये किस्में सहायक सिद्ध हुई हैं।

खाद्य तेलों की कमी

1135. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31 अक्तूबर, 1990 के "फाइनैन्सियल एक्सप्रेस में "एडीबुल आयल शार्टेज टू टच 13 एल.टी. इन 1990-91" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष देश में खाद्य तेलों के उत्पादन के बारे में सरकार के क्या अनुमान हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस वर्ष देश में खाद्य तेल की खपत के बारे में कोई मूल्यांकन किये हैं ; और

(घ) सरकार दालों की मांग और पूर्ति के बीच के अंतर को कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार रखती है ;

कृषि मंत्रालय में और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयन्ती लाल वीरचन्द भाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) खरीफ तिलहनों का उत्पादन अनुमानतः 87 लाख मीटरी टन है । रबी में उत्पादन की आशा अनुकूल है परन्तु वर्तमान चरण पर पक्के अनुमान देना संभव नहीं है । इसलिये इस समय यह कहना संभव नहीं है कि इस वर्ष देश में खाद्य तेलों का उत्पादन कितना होगा ।

(ग) तेल वर्ष 1990-91 में देश में खाद्य तेल की मांग करीब 60 लाख मीटरी टन होने की आशा है ।

(घ) सरकार, तिलहनों के उत्पादन और खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने के लिये तिलहन उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है । तिलहन परिसंस्करण और निष्कर्षण की क्षमता बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं । इस अंतर को कम करने के लिये खाद्य तेल के आयात पर भी विचार किया गया है ।

दिल्ली में वनस्पति के मूल्यों में वृद्धि

1136. **श्री बलराम सिंह यादव :**
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 अक्तूबर, 1990 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "शार्प इनक्रीज इन वनस्पति प्राइसेस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और यदि हां, तो दिल्ली में जुलाई, 1990 से अक्तूबर, 1990 के बीच वनस्पति के मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि 1990 में त्यौहारों के मौसम के दौरान वनस्पति के दामों में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में अक्तूबर, 1990 में वनस्पति के मूल्य क्या थे ; और

(घ) मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या हाल में प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं ?